



# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



**4** अशोक महलोट ने डांगवास हत्याकांड में फैसले को बेहद चिंताजनक बताया

**6** 'धुरंधर' पर अखिलेश की माराजगी के सियासी मायने

**7** मॉडलिंग क्या होती है, ये भी नहीं जानती थीं : तनुश्री चक्रवर्ती

## फर्स्ट टेक

**बांग्लादेश में 20 अगस्त को होगा राष्ट्रपति चुनाव**

ढाका/भाषा। बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग ने बुधरूपितवार को घोषणा की कि देश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को कराया जाएगा। सत्ता से अपवस्थ की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के लंबे समय से सहयोगी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपना कार्यकाल पूरा होने से दो साल पहले ही 24 जुलाई को पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति चुनाव अपरिहार्य हो गया था। निर्वाचन आयोग सचिवालय के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने बुधरूपितवार को बताया कि मतदान 20 अगस्त को अपराह्न 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जातीय संसद के सत्र कक्ष में होगा। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के मुताबिक, अहमद ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद से बातचीत के बाद की गई। हाफिज उद्दीन अहमद संविधान के तहत 90 दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं।

**नौका दुर्घटनाग्रस्त, श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को बचाया**

कोलंबो/भाषा। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में एक नौका के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बुधरूपितवार को श्रीलंकाई नौसेना ने 11 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। यह दुर्घटना श्रीलंका के उत्तरी तट के पास पाक जलडमरूमध्य में स्थित डेलफ्ट द्वीप (जिसे नेदुथिपु भी कहा जाता है) की तटीय मृंगा चट्टान (कोस्टल रीफ) के पास हुई। श्रीलंका नौसेना के अनुसार, यह नौका बुधवार देर रात अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करके श्रीलंका के जलक्षेत्र में प्रवेश कर गई थी और कथित तौर पर चट्टान से टकराकर वहां फंस गई।

**मेटा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, एल्गोरिदम और भारतीय कानूनों के पालन पर सरकार सख्त**

नई दिल्ली/भाषा। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा के अधिकारियों से बुधरूपितवार को लगातार दूसरे दिन भारत सरकार के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान इंस्टाग्राम के कंटेंट सुझाव संबंधी एल्गोरिदम और भारतीय कानूनों के अनुपालन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया कंपनियों को संचालन करने वाली कंपनी मेटा के अधिकारियों ने सरकार को आश्चर्य किया है कि वह डीपफेक और यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) और बांट खातों से निपटने के लिए काम कर रही है।

07-07-2026 08-08-2026  
सूर्यास्त 6:45 बजे सूर्योदय 6:08 बजे

BSE 78,581.00 (+152.05)  
NSE 24,624.65 (+9.75)  
सोना 15,832 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम  
चांदी 231,439 रु. प्रति किलो

**मिशान मंडेला**

**दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक  
epaper.dakshinbharat.com



कैलाश मण्डेला, मो. 9828234344

**ये जो पब्लिक है**

अब आत्म मुध्ता प्रवंचना का, कैसा है यह अजब दौर। खुद को सब समझे साहुकार, दूजों को कहते चोर-चोर। वादे इनके तो हैं सपने, उनकी बातें हैं सिर्फ शोर। सच तो होता सूरज जैसा, जनता करती है सदा गौर।।



**तेजपाल दोषी कराया, 10 साल की सजा**

**उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को अनुचित बताया**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

पणजी/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 के बलात्कार मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए बुधरूपितवार को निचली अदालत के बरी करने के फैसले को अनुचित करार दिया। उच्च न्यायालय ने साथ ही कहा कि निचली अदालत इस धारणा का शिकार हो गई कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को "आदर्श पीड़िता" होना चाहिए और उसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति अमित जमसांडेकर की पीठ ने 81 पृष्ठों के फैसले में बचाव पक्ष द्वारा पीड़िता को कठघरे में खड़ा करने और उसके निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि निचली अदालत ने जिरह के दौरान बचाव पक्ष को उसे "परेशान और अपमानित" करने दिया। उच्च न्यायालय ने तेजपाल को बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि पीड़िता ने सत्य बयान दिए और अभियोजन पक्ष ने अपना मामला हर तरह के "संदेह से परे" साबित किया।



**झारखंड परीक्षा आंदोलन 13वें दिन भी जारी**

रांची/भाषा। झारखंड में भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधरूपितवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गया और इस दौरान छह प्रदर्शनकारी अनशन पर हैं। वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार के साथ बातचीत करके गतिरोध दूर करने के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गठित किया। प्रदर्शन की गूंज बुधरूपितवार को राज्य विधानसभा तक पहुंची, जहां मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने परिसर में नारेबाजी करके छात्रों की मांगों का समर्थन किया। यह प्रदर्शन

25 जुलाई को यहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 'जे पीएससी-जे एसएससी रीफॉर्मर्स मंच' के बैनर तले शुरू हुआ था और हाल के वर्षों में राज्य के सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बन गया है। जे पीएससी-जे एसएससी रीफॉर्मर्स मंच के एक पदाधिकारी ने कहा, सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव के जवाब में हमने 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया है, जिसमें आठ छात्र, दो विशेषज्ञ और एक अधिवक्ता शामिल हैं। सरकार के साथ बातचीत का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बुधवार को दिए गए बयान के एक दिन बाद लिया गया।

**विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा**



**चर्चा के लिए उपलब्ध हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह : किरेन रीजीजू**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधरूपितवार को विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज नहीं चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे दिन संसद में मौजूद रहते हैं और चर्चा के लिए उपलब्ध रहते हैं। रीजीजू ने कहा कि संसद में गतिरोध के बावजूद विधायी कामकाज जारी है और विधेयक पारित किए जा रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों

**विपक्ष सदन का कामकाज रोक रहा है, जबकि आरोप यह लगा रहा है कि सरकार बहस से बच रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही संसद में मौजूद रहते हैं और शाम को ही जाते हैं।**

की कार्यवाही अवरुद्ध बनी हुई है। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए रीजीजू ने कहा कि विपक्ष सदन का कामकाज रोक रहा है, जबकि आरोप यह लगा रहा है कि सरकार बहस से बच रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही संसद में मौजूद रहते हैं और शाम को ही जाते हैं। विपक्ष ही सदन का कामकाज नहीं चलने दे रहा है और बाहर नारे लगा रहा है। यह सही नहीं है। रीजीजू ने कहा कि सरकार ने सदन में कामकाज

करने और विधेयक पारित कराने का काम जारी रखा है, खासकर राज्यसभा में, जहां विपक्ष के सदस्यों के विरोध के बावजूद चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, "हम विधेयक पारित कर रहे हैं और सदन का कामकाज चला रहे हैं। राज्यसभा में उचित चर्चा के बाद विधेयक पारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस और उसके एक-दो सहयोगी दल भले ही सदन से वॉकआउट कर रहे हों या हंगामा कर रहे हों, लेकिन सदस्य चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं।" संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया

कि लगातार हो रहे व्यवधान से सरकार के बजट कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर उसके पहली बार सांसद बने नेताओं को संसद में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए पहले ही 'क्रांतिकारी' कदम उठाए हैं और विपक्ष इसी मुद्दे को लेकर बार-बार विरोध-प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, "यह मुद्दा खत्म हो चुका है। देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक पर क्रांतिकारी फैसले लिए हैं।"

**नेतन्याहु ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन**

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बुधरूपितवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु ने फोन किया और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की तथा दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नेतन्याहु और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर बातचीत की। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।" पश्चिम एशिया में संघर्ष बिना किसी स्थायी समाधान के पांच महीने से अधिक समय से जारी है।

ईरान ने बुधरूपितवार को कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में इजराइल के दो सैनिक मारे गए हैं। यह जलडमरूमध्य वैश्विक पोत परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले, दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस फास की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस जलमार्ग से होकर गुजरता था।

**सरकार ने संवेदनशील ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय-सीमा घटाकर दो घंटे की**

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने सोशल मीडिया मंचों के लिए संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय-सीमा 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दी है। बुधरूपितवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, इस साल 10 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 में संशोधन किए गए थे ताकि कृत्रिम रूप से तैयार जानकारी जैसे डीपफेक और एआई-जनित सामग्री से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए नियामकीय ढांचे को मजबूत किया जा सके। बयान में कहा गया, इसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को और सख्त किया गया है। वैध कारणों

के साथ सरकार या अदालत के आदेश मिलने पर अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। वहीं शिकायत निवारण की समय-सीमा (अन्फ़ीलता एवं प्रतिरूपण जैसे विशेष मामले) 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दी गई है। आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख सोशल मीडिया मंचों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे उचित तकनीकी उपाय, जैसे स्वचालित उपकरण या अन्य व्यवस्था लागू करें ताकि बलात्कार और बाल यौन शोषण से संबंधित या पहले हटाई जा चुकी समान सामग्री को पहचान सक्रिय रूप से की जा सके।

**‘गोबरधन’ के लिए 23,731 करोड़ रुपए की मंजूरी**

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन में तेजी लाने के लिए बुधरूपितवार को 23,731 करोड़ रुपये की एक राष्ट्रीय एकीकृत योजना को मंजूरी दी।

यह योजना आयतित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और स्वच्छ ऊर्जा बदलाव को मजबूत करने के लिए कृषि एवं शहरी कचरे के उपयोग पर आधारित है। सरकार

ने एक बयान में कहा कि 'गोबरधन' (जैविक संसाधनों से धन सृजन) योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 के बीच लागू की जाएगी।

इसका लक्ष्य सुनिश्चित खरीद, विनियमित मूल्य, पूंजी सब्सिडी, पाइपलाइन अवसंरचना और वित्त तक आसान पहुंच के जरिए घरेलू सीबीजी उत्पादन को लाभग दस गुना बढ़ाना है।

OPENS TODAY  
THE  
NEW STANDARD IN STYLE



OVER 250+ TOP LABELS

7.8.9  
AUG

THE  
LaLiT  
ASHOK  
BANGALORE

10 am - 8 pm | Valet Parking | Entry fee Rs.100







दूधरी और सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए दली भी पहरेदार रहे। उन्होंने कहा कि जब कभी आपम कार्यकाल पूरा करके आए आप नागरिक के तौर पर जीवन जीते हैं, तो ये समाज और सेना के बीच “एक जीवंत सेतु” की भूमिका निभाते हैं और लोगों, खासकर युवाओं को रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रादेशिक सेना एक प्रशिक्षित और मजबूत बल है, जिसमें लगभग 44,400 कर्मी और 59 अलग-अलग इकाइयां शामिल हैं। प्रादेशिक सेना का गठन 9 अक्टूबर 1949 को हुआ था। देशकों के अपनी यात्रा के दौरान इन्हें युद्ध के समय और मानवीय व पर्यावरण संरक्षण में देश की सेवा की है।

ने कहा, "प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जानवरों को बचाने के काम पर अक्सर रतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। जो लोग इस नए काम के लिए आगे आए हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। श्री अनंत अंबानी के इस विचारशील और दयालु कदम के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।" असम में बाढ़ से कम से कम 95 लोगों की मौत हुई है और करीब 1.6 लाख प्रभावित हुए हैं।



मुस्कान एक ऐसी भाषा है, जिसे हर कोई समझता है। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, जीवन आसान लगेगा।

## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

### बांग्लादेश में ‘तूफान’ की आहट

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में स्वदेश लौटने की घोषणा कर इस पड़ोसी देश के राजनीतिक गतिyarों में हलचल मचा दी है। अगर वे अपने फैसले पर अडिग रहेंगी और बांग्लादेश लौटेंगी तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस घटना का असर भारत-बांग्लादेश के संबंधों पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पूरी कोशिश होगी कि शेख हसीना स्वदेश न लौटें। उनकी सरकार दबाव बनाने में जुट जाएगी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के बांग्लादेश लौटने से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को नई ऊर्जा मिलेगी। हो सकता है कि उस स्थिति में शेख हसीना को हवाईअड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया जाए! उनके खिलाफ अदालतों में कई मामले लंबित हैं। कुछ नए मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को शांति के लिए खतरा बताकर हवाईअड्डे से ही जेल भेज सकती है। बांग्लादेशी समाज अपने तीव्र विरोध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। वहां ऐसी घटनाओं में भारी हिंसा का इतिहास रहा है। जब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक यह खबर फैलेगी कि शेख हसीना आ रही हैं तो उनके समर्थक और विरोधी, दोनों में भयंकर टकराव हो सकता है। इन घटनाओं का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बांग्लादेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर सकती है। अगर हालात बेकाबू हुए तो कई लोग भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सीमा पर तैनात हमारे सुरक्षा बलों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शेख हसीना के समर्थक उनके भव्य स्वागत की तैयारियां करेंगे, कुछ ही पूर्व प्रधानमंत्री उन तक न पहुंचें। वे उनके सम्मान में जुलूस और जनसभाओं का आयोजन करेंगे। बांग्लादेश सरकार उन्हें रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाएगी।

जिन कथित आंदोलनकारियों ने अगस्त 2024 में उपद्रव मचाया था, वे दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि, इस बार उनकी भूमिका कुछ अलग हो सकती है। वे उस हवाईअड्डे पर धावा बोल सकते हैं, जहां शेख हसीना का विमान उतरेगा। यही नहीं, उन्हें जेल ले जाने की स्थिति में उस इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर, समर्थकों के घर भी चपेट में आ सकते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि कट्टरपंथी तत्त्व उन पर हमला करने के लिए ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं। बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को अपने घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उनके आस-पास सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाने चाहिए। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ, महत्वपूर्ण दूतावासों, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को ईमेल भेजकर अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश सरकार पर दबाव पड़े और वह उन इलाकों की सुरक्षा की ओर ध्यान दे। भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स को यह मुद्दा जोर-शोर से उठाना चाहिए। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जाय के ये शब्द असल हालात को बयान करते हैं- ‘अगस्त 2024 से बांग्लादेश में राजनीतिक हत्याओं को वैध बना दिया गया है। आज बांग्लादेश एक विफल राष्ट्र है और वहां कानून व्यवस्था नहीं है। नई दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि भारत की पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है।’ शेख हसीना को हटाने के पीछे गहरी साजिश थी। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेश के आम लोगों को हुआ है। जो देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसे ग्रहण लग गया है। कट्टरपंथियों की पौ-बारह हो गई है। यह स्थिति पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंताजनक है। भारत सरकार को अपना किरदार बहुत मजबूती से निभाना होगा।

## ट्वीटर टॉक



‘सबका साथ-सबका विकास’ का मंत्र आज समाज के हर वर्ग के उत्थान का कारण बन गया है। उत्थान की इस यात्रा का आधार ‘घुमंतू विकास बोर्ड’ है। म घुमंतू समाज द्वारा घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

—योगी आदित्यनाथ

आज एफएलओ कलेक्टिव 2026 एग्जिबिशन में शामिल हुआ, यह नेशनल हेंडलूम डे की सच्ची भावना के साथ आयोजित एक मौका था, जिसमें महिला सशक्तिकरण और हमारे कारीगरों के अमूल्य योगदान का जश्न मनाया गया।

—दिया कुमारी



डांगवावास हत्याकांड मामले में 11 साल बाद आया फैसला बहुत चिंता की बात है। 2015 में, जमीन के झगड़े में पांच दलितों समेत छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और अब उच्च-ऊच्च स्पेशल कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है।

—अशोक गहलोत

## प्रेरक प्रसंग

### लोभ और आत्मसंयम

एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से पूछा ‘गुरुदेव! चरक संहिता में अनेक स्थलों पर लोभ को रोकने की बात कही गई है और इसका संबंध रोगों से भी जोड़ा गया है, लेकिन मन में उत्पन्न होने वाली इस प्रवृत्ति को आखिर रोका कैसे जाए?’ गुरुजी ने सीधे उत्तर देने के बजाय उससे पूछा, ‘बताओ, हम अपनी आवश्यकता से अधिक जितना भी धन, वस्तुएं और साधन जीवन भर संचित करते हैं, क्या वे अंत में हमारे साथ जाते हैं?’ शिष्य ने उत्तर दिया, ‘नहीं गुरुदेव!’ गुरुजी बोले, ‘बस, इसी ‘नहीं’ को यदि मनुष्य समय रहते समझ ले तो लोभ पर नियंत्रण की शुरुआत हो सकती है। इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक अंग हैं और मनुष्य को कर्म तथा प्रगति के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकताओं से बहुत आगे निकल जाती हैं तो वे लोभ का रूप धारण कर लेती हैं। लोभ की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं होती। इसलिए लोभ को रोकने का अर्थ इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, बल्कि विवेक और आत्मसंयम द्वारा उन्हें अपने ऊपर नहीं होने देना है। लोभ को कम करने का एक प्रभावी उपाय दान और बांटने की प्रवृत्ति भी है। संग्रह मन को संकुचित करता है, जबकि दान मन का विस्तार करता है।’

## महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company/6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekanth Parashar.** (\*Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn.No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पातों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरादेई नहीं बना सकता। — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु | शुक्रवार | 07-08-2026



www.dakshinbharat.com



/dakshinbharat



/dakshinbharat

DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

## सामयिक

# संसदीय-गतिरोध : संवाद ही है समाधान

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

**भा**रतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। यही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श होता है, सरकार जवाबदेह बनती है, विपक्ष जनभावनाओं को स्वर देता है और कानूनों के माध्यम से देश के विकास की दिशा तय होती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद संवाद और सहमति का मंच बनने के बजाय टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक हठधर्मिता का अखाड़ा बनती जा रही है। मानसून सत्र में जिस प्रकार लगातार गतिरोध बना हुआ है, उससे केवल संसदीय कार्यवाही ही बाधित नहीं हो रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी आहत हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति लातती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक आग्रहों में डूबते उलझ गए हैं कि राष्ट्रहित पीछे छूट गया है। विपक्ष की ओर से यह शर्त रखी जा रही है कि जब तक कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार सदन में बयान और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अडिग है। परिणाम यह है कि संसद का बहुमूल्य समय निरर्थक विवादों की भेंट चढ़ रहा है।

लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति को अराजकता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है, परंतु संसद को ठप कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है। जब विरोध संसद को चलने की न दे, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक



दायित्वों की उपेक्षा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है कि संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से उछाले जाते हैं, जिनके आधार पर पूरे सत्र को बाधित किया जा सके। परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं अथवा कई विधेयक लंबित रह जाते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान देश को होता है। संसद का प्रत्येक मिनट करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से संचालित होता है। यदि वह समय केवल शोर-शराबे और नारेबाजी में बीत जाए तो यह कर्दाताओं के धन और लोकतांत्रिक शिक्षास-दोनों का अपमान है।

लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय राजनीति की श्रेष्ठ परंपरा संवाद, सहमति और संवेदनशीलता की रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने दुराग्रह छोड़कर संवाद की मेज पर बैठें। संसद की गरिमा इस बात में नहीं है कि कौन कितने अधिक कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इस बात में है कि राष्ट्रहित के प्रश्नों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल आंदोलन और विरोध का नाम नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि

लोकतंत्र को संभालने की होती है। यदि प्रत्येक मुद्दे पर संसद को बाधित करने की रणनीति अपनाई जाएगी तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नीति और दृष्टि का अभाव है। लोकतंत्र में जनता केवल विरोध नहीं, समाधान भी चाहती है। यदि विपक्ष स्वयं संवाद से दूरी बनाएगा तो संवाद से समाधान का आदर्श केवल नारा बनकर रह जाएगा।

सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता। सरकार को भी विपक्ष की उचित मांगों को सुनना चाहिए और जहां संभव हो, सहमति का मार्ग निकालना चाहिए। संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। इसलिए सरकार को भी संवेदनशीलता, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। किंतु यदि संवाद का प्रत्येक प्रयास केवल राजनीतिक शर्तों और हठधर्मिता में उलझ जाए तो समाधान की संभावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक परिपक्वता की है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर मुद्दे को चुनावी लाभ-हानि के चश्मे से देखा जा रहा है। संसद में बहस कम और राजनीतिक संदेश अधिक दिए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद का उद्देश्य जनकल्याणकारी नीतियों पर विचार करना

## मंथन

# ‘धुरंधर’ पर अखिलेश की नाराजगी के सियासी मायने

अजय कुमार

मोबाइल : 9335566111

**सि**नेमा और राजनीति का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है, लेकिन जब परदे की कहानियां सीधे तौर पर चुनावी मैदान के समीकरणों और राजनीतिक दलों के इतिहास को प्रभावित करने लें, तो सियासत गरमाना लाजिमी है। हाल ही में रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त सफलता हासिल करने वाली फिल्म धुरंधर को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने इस फिल्म को सीधे तौर पर एक सरकारी प्रोपेगेंडा करार देते हुए यह तक कह दिया है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी। आखिर क्या वजह है कि एक कमर्शियल फिल्म पर सूबे के इतने बड़े राजनेता को इतनी कड़ी आपत्ति जतानी पड़ी और क्यों उन्होंने सरकार बनने पर जांच की बात कहकर राजनीतिक दांव चला है, इसे वर्तमान और अतीत के राजनीतिक घटनाक्रम के आईने में आसानी से समझा जा सकता है।

इस पूरे विवाद की जड़ में यह किरसा है जिसका इस्तेमाल हालिया दौर के राजनीतिक नैरेटिव को गढ़ने के लिए किया जा रहा है। दरअसल, फिल्म धुरंधर और इसके सीक्वेंस में पूर्वांचल के एक चर्चित माफिया डॉन के किरदार और उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा आतंकी संगठनों के साथ संबंधों को परदे पर दिखाया गया है। यह किसी से छिपा नहीं है कि उक्त माफिया राजनेता अतीत में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर



विधानसभा तक पहुंच चुका था। राजनीतिक विरोधियों ने इस सिनेमैटिक प्लॉट का इस्तेमाल तुरंत समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए हथियार के रूप में करना शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लगे उन पोस्टरों और विज्ञापनों ने आग में घी का काम किया, जिनमें सपा के पुराने शासनकाल की तुलना फिल्म के काल्पनिक और अराजक ‘राज’ से कर दी गई। जब किसी दल के पूरे राजनीतिक अतीत, उसकी कार्यप्रणाली और पुराने दौर के दागों को बड़े परदे के जरिए जनमानस के बीच इस तरह परोसा जाए कि सीधा संबंध किसी खास दल से जुड़े होने का आभास हो, तो दल के मुखिया के लिए उस पर प्रतिक्रिया देना राजनीतिक मजबूरी बन जाता है।

अखिलेश यादव का यह आक्रामक रुख महज एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भाजपा सरकार पर विपक्षियों की छवि धूमिल करने के

लिए सरकारी तंत्र और संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता रहा है। अखिलेश ने यह सवाल उठाकर कि इस तरह के फिल्म निर्माण में भारी-भरकम पैसा कहां से आ रहा है और कौन लोग इसके पीछे हैं, एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उनका यह बयान इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी अब वैचारिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी आक्रामक तैवर अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। जब राजधानी में विपक्षी खेमे द्वारा लगातार ऐसे पोस्टर चरपा किए जाएं जो पार्टी के पुराने शासनकाल को अपराध और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ के रूप में चित्रित करें, तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इन हमलों को सिर्फ जुबाबी जमाखर्च से न टाटें, बल्कि भविष्य की सत्ता का विश्वास दिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखें और विरोधियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दें। सरकार बनने पर फिल्म निर्माण और इसके वित्तपोषण की जांच करए जाने की बात कहकर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के समर्थकों और कैड्स को भी एक कड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों, कानून-व्यवस्था के मुद्दों और ब्राह्मणों के उत्पीड़न जैसे अन्य समकालीन मुद्दों के बीच, ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों के जरिए बन रहे नैरेटिव को काउंटर करना समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा बन गया है। अखिलेश भली-भांति समझते हैं कि यदि जनता के बीच इस प्रोपेगेंडा का माकूल जवाब समय रहते नहीं दिया गया, तो यह उनकी पार्टी की संक्युलर और प्रगतिशील छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने आक्रामक रुख अपनाने हुए स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता परिवर्तन होने पर केवल वर्तमान नीतियां ही नहीं, बल्कि इस प्रकार के राजनीतिक छद्म युद्धों और उनके वित्तीय स्रोतों की परतों को भी कानूनी दायरे में बेनकाब किया जाएगा।

## नजरिया

# गिरता भाषाई स्तर : संस्कृति, संस्कार और सामाजिक बोध का संकट

डॉ स्नेहलता श्रीवास्तव

**म**नुष्य का निर्माण केवल रक्त-मांस और अस्थियों से नहीं होता। उसका वास्तविक गठन उन सूक्ष्म संस्कारों, अनुभूतियों और सांस्कृतिक संकेतों से होता है जो पीढ़ियों के जीवन-अनुभव से घनकर उसकी चेतना में उत्तरते हैं। इसीलिए किसी समाज को समझने के लिए उसकी भाषा को पढ़ना अनिवार्य माना गया है। भाषा मनुष्य के संस्कारों, संवेदनाओं और सांस्कृतिक अनुशासन का दर्पण है। किसी सभ्यता की आत्मा उसकी भाषा में निवास करती है। शब्द केवल ध्वनियाँ नहीं होते; वे इतिहास की स्मृतियाँ, संस्कृति की परंपराएँ और समाज के नैतिक मूल्य अपने भीतर संजोए रहते हैं। किसी व्यक्ति की भाषा उसके पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक परिवेश, अध्ययन, संवेदनशीलता और मानसिक परिपक्वता का परिचय देती है।वह वक्ता के आंतरिक संसार का प्रतिबिम्ब है।

भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्म और वाणी को सरस्वती का आचान माना गया। यह केवल

आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी; उसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक समझ थी। हमारे ऋषि जानते थे कि मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बोलता है और जैसा बोलता है, धीरे-धीरे वैसा ही बनता जाता है। शब्द केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करते, वे विचारों का निर्माण भी करते हैं। इसीलिए सभ्यता का प्रारंभ वाणी के अनुशासन से होता है। जब कोई बालक बोलना सीखता है तो वह केवल शब्द नहीं सीखता, वह सम्मान करना, संबोधन करना, संबंधों का मूल्य समझना और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना भी सीखता है।

उसकी भाषा में घर का वातावरण बोलता है, माता-पिता की संवेदना बोलती है, पीढ़ियों का

अनुभव बोलता है। भाषा संस्कृति का वह अदृश्य सेतु है जो व्यक्ति को समाज से और समाज को अपनी परंपरा से जोड़ता है। किन्तु आज इसी सेतु में दरारें पड़ती दिखाई देने लगी हैं। सार्वजनिक जीवन, राजनीति, मनोरंजन और विशेष रूप से सोशल मीडिया ने भाषा के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया है। संवाद की जगह प्रतिक्रियाएँ ले रही हैं, विचार-विमर्श की जगह आरोप-प्रत्यारोप और तर्क की जगह उत्तेजना। शब्दों की गरिमा से अधिक उनके प्रहार की क्षमता को महत्व मिलने लगा है। कटुता को स्पष्टवादिता, अभद्रता को निर्भीकता और अपमान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर्याय माना जाने लगा है।

इतिहास साक्षी है कि जिन समाजों ने अपनी भाषा की मर्यादा खोई, उन्होंने धीरे-धीरे अपने सांस्कृतिक संतुलन को भी खो दिया। सभ्यता का क्षरण अचानक नहीं होता; वह शब्दों से आरंभ होकर व्यवहार तक पहुंचता है और व्यवहार से मूल्य-व्यवस्था तक। इसलिए भाषा की चिंता वस्तुतः संस्कृति की चिंता है, वाणी की रक्षा वास्तव में मनुष्यता की रक्षा है। आज आवश्यकता केवल शुद्ध भाषा की नहीं, शुद्ध चेतना की है। परिवारों में संवाद की संस्कृति लोटे, साहित्य शब्दों की गरिमा का पुनः स्मरण कराए, शिक्षा व्यक्तित्व और वाणी के संबंध को समझाए तथा समाज यह स्वीकार करे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभद्रता समानार्थी नहीं हैं। शब्दों की मर्यादा कोई बंधन नहीं, बल्कि सभ्यता का सौंदर्य है। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों, वैभव या उपलब्धियों से पहले उसकी वाणी से होती है। भाषा वक्ता के मानसिक स्तर का प्रतिबिम्ब होती है। शब्दों की शालीनता में ही संस्कृति का माधुर्य, समाज की संवेदना और मनुष्य की गरिमा सुरक्षित रहती है। इसलिए भाषा का प्रश्न केवल भाषाविदों का प्रश्न नहीं, सम्पूर्ण सभ्यता के भविष्य का प्रश्न है।इस दिशा में सभी को समय रहते चिंतन करना चाहिए।



